भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1462

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तेल का आयात

1462 श्री सु. वेंकटेशन:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिकी टैरिफ से भारत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत से कृषि और चिकित्सा उत्पादों का अधिक आयात करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है;
(ख) यदि हाँ, तो केंद्र सरकार द्वारा रूस की सरकार को दी गई प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में रूस की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;
(घ) क्या यह सही है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण देश ने रूस से तेल आयात में कटौती शुरू कर दी है;
(ङ) वर्ष 2024 और 2025 के लिए तेल से हुए आर्थिक प्रभाव की माह-वार तुलनात्मक तालिका क्या है; और
(च) क्या यह सही है कि पाँच प्रमुख रिफाइनरियों ने दिसंबर 2025 में रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत और रूसी संघ एक मज़बूत रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हैं, जिसकी पहचान व्यापार और आर्थिक सहयोग पर नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत से होती है। द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मामलों, जिसमें ट्रेड बास्केट में विविधता लाने और भारतीय

निर्यात को बढ़ाना शामिल है, पर भारत-रूस अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से चर्चा की जाती है। सरकार कृषि और चिकित्सा उत्पादों सहित भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुँच को सुगम बनाने हेतु रूसी पक्ष के साथ मिलकर काम करती है।

(घ) और (च) : भारत में कच्चे तेल का आयात भारतीय रिफाइनरियों द्वारा विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक, बी2बी आधार पर, तकनीकी-व्यावसायिक विचारों द्वारा निर्देशित होकर किया जाता है। जबकि सरकार नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तेल आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोत्साहित करती रही है, लेकिन किसी विशेष देश या क्षेत्र से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा के बारे में निर्णय कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जाता है, और सरकार उनके वाणिज्यिक खरीद विकल्पों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ड.): कच्चे तेल के आयात का आवधिक ब्यौरा वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे https://ftddp.dgciskol.gov.in/dgcis/ पर देखा जा सकता है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1462

<u>दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

तेल का आयात

1462 श्री सु. वेंकटेशन:
श्री तमिलसेल्वन थंगा:
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिकी टैरिफ से भारत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत से कृषि और चिकित्सा उत्पादों का अधिक आयात करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो केंद्र सरकार द्वारा रूस की सरकार को दी गई प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रूस की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या यह सही है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण देश ने रूस से तेल आयात में कटौती शुरू कर दी है;

(ङ) वर्ष 2024 और 2025 के लिए तेल से हुए आर्थिक प्रभाव की माह-वार तुलनात्मक तालिका क्या है; और

(च) क्या यह सही है कि पाँच प्रमुख रिफाइनरियों ने दिसंबर 2025 में रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत और रूसी संघ एक मज़बूत रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हैं, जिसकी पहचान व्यापार और आर्थिक सहयोग पर नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत से होती है। द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मामलों, जिसमें ट्रेड बास्केट में विविधता लाने और भारतीय

निर्यात को बढ़ाना शामिल है, पर भारत-रूस अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से चर्चा की जाती है। सरकार कृषि और चिकित्सा उत्पादों सहित भारतीय उत्पादों के लिए बाज़ार पहुँच को सुगम बनाने हेतु रूसी पक्ष के साथ मिलकर काम करती है।

(घ) और (च) : भारत में कच्चे तेल का आयात भारतीय रिफाइनरियों द्वारा विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक, बी2बी आधार पर, तकनीकी-व्यावसायिक विचारों द्वारा निर्देशित होकर किया जाता है। जबकि सरकार नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तेल आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोत्साहित करती रही है, लेकिन किसी विशेष देश या क्षेत्र से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की मात्रा के बारे में निर्णय कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से लिया जाता है, और सरकार उनके वाणिज्यिक खरीद विकल्पों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

(ङ.): कच्चे तेल के आयात का आवधिक ब्यौरा वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे https://ftddp.dgciskol.gov.in/dgcis/ पर देखा जा सकता है।

****